साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 23-29 मई 2022, वर्ष-8, अंक-8

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

जिम्मेदार मौन: प्रदेश के किसान कर रहे जहरीली मूंग की खेती, बेखौफ कर रहे कीटनाशक का उपयोग

» पूर्व विस अध्यक्ष बोले-हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी

» नर्मदापुरम में 4 लाख हेक्टेयर में मूंग, कृषि मंत्री खुद भी स्वीकार रहे

संभल जाओ! वरना जहरीली फसल जमीन को 10 साल में बना देगी बंजर

भोपाल। संवाददाता

जो मूंग दाल सबसे पौष्टिक मानी जाती है, वो अब जहरीली होती जा रही है। प्रदेश में मूंग की जितनी भी खेती होती है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा नर्मदापुरम संभाग में उग रहा है, लेकिन यहां के किसान पूरी फसल को दो महीने में पकाने के लिए चार बार और 12 घंटे में सुखाने के लिए एक बार कीटनाशक छिड़क रहे हैं। इससे फसल का दाना तो हरा बना रहता है, लेकिन वो हार्वेस्टर से आसानी से कट जाती है। अभी प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर में 1 करोड़ 35 लाख क्विंटल मूंग पैदा करने के लिए किसान यही तकनीक अपना रहे हैं। इससे न केवल सरकार परेशान है, बल्कि कृषि वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जहरीली फसल जमीन को 10 साल में बंजर बना देगी। वहीं मप्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा का कहना है कि ये फसल नहीं जहर है। मैं तो हर सभा में किसानों को समझा रहा हूं कि कीटनाशक की ऐसी खेती हमारी नस्लें खराब कर देगी, लेकिन किसान है कि मान ही नहीं रहे हैं। सरकार ही कोई ठोस कदम उठाए।

हेक्टेयर में मूंग का रकबा

वर्ष	नर्मदापुरम	हरदा	बैतूल
2018	81970	12200	850
2019	91000	12000	410
2020	182262	82500	3050
2021	228000	82500	4000
2022	232705	135000	3900
2023	330000	190000	10000

नोट-कृषि विभाग के अनुसार 2023 का रकबा

कृषि मंत्री दिला रहे संकल्प

बड़ी बात है कि कृषि मंत्री कमल पटेल भी किसानों से इस जहर की खेती को बंद करने की बात कर रहे हैं, लोगों को ऐसे जहर की खेती न करने का संकल्प दिला रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि किसान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो मूंग उगा रहे हैं-वे भी इसे नहीं खाते।

इसलिए डालते हैं कीटनाशक

किसान मूंग की बोवनी देरी से करते हैं और जल्दी फसल उगाने के लिए बार-बार कीटनाशक डालते हैं। जैविक खेती में मूंग की फसल 2 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन आधी फसल इल्लियां खा जाती हैं या फिर झड़ जाती है। कीटनाशक डालने से पैदावार 95 फीसदी तक हो जाती है।

किसान ही मान रहे जहरीली

बीलाखेड़ी के किसान कहते हैं कि 25 एकड़ में मूंग लगी है। एक एकड़ में 7 क्विंटल मूंग चाहिए तो दवाई तो डालना पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जुझारपुर के किसान का कहना है कि हम ये मूंग नहीं खाते। गुनौरा के यज्ञदत्त गौर, जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष नवल पटेल कहते हैं कि इस मूंग को कैसे खा सकते हैं। ये जहरीली है।

देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन नर्मदापुरम संभाग में है। अभी यहां 5 लाख हेक्टेयर में गेहूं और 4 लाख हेक्टेयर में मूंग उग रही है। अगले साल 5 लाख हेक्टेयर में होगी। इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी तो किसानों ने ज्यादा कीटनाशक डाला। मैं तो किसानों को संकल्प दिला रहा हूं कि ये जहरीली खेती न करें। अभी नहीं रुके तो पंजाब जैसे हालात होंगे। कोरोनाकाल जैसी कैंसर रोगियों की भरमार होगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

जमीन के जैविक तत्व जल रहे हैं। यहां के 100 प्रतिशत किसान जहरीली मूंग उगा रहे हैं। 10 साल में ये क्षेत्र पंजाब बन जाएगा। हर घर में कैंसर रोगी होगा। वैकल्पिक फसल का रास्ता कुछ कमाई और जमीन उपजाऊ रखने के लिए था, लेकिन किसानों ने जो तरीका अपनाया, वो घातक है।

सुनील कुमार धोटे, कृषि सहायक संचालक, नर्मदापुरम

रासायनिक खाद का असर जमीन में जाने के बाद पानी पर, जानवरों के चारे पर, दूध पर भी हो रहा है। एक बार कीटनाशक डालने पर इसका 5 साल तक मिट्टी में असर खत्म नहीं होता है। मूंग के साथ अभी जो हो रहा, उस पर तत्काल बैन लगाना चाहिए वरना खून, लिवर, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी।

डॉ. अमित कुमार शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विवि, जबलपुर

सीएम बोले-किसान प्राकृतिक खेती एवं कृषि का विविधीकरण करें

मप्र के 82 लाख किसानों को मिली सम्मान निधि

› रीवा में 3.70 लाख हितग्राहियों को दिए स्वामित्व अधिकार अभिलेख

भोपाल। संवाददाता

सरकार का लक्ष्य है कृषि को लाभ का धंधा बनाना। किसान कृषि का विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती करें। इससे उनको अधिक मुनाफा होगा तथा कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी। सरकार प्राकृतिक खेती के लिए किसान को एक गाय रखने पर 900 रुपए प्रतिमाह देगी। गोबर, गौ-मूत्र, गुड़ आदि के मिश्रण से तैयार किए जाने वाला जीवामृत मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में स्वामित्व योजना में प्रदेश के 3.70 लाख ग्रामीणों को आबादी अधिकार अभिलेखों के वितरण समारोह के दौरान कही। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 82 लाख किसानों के खातों में 4-4 हजार रुपए की सम्मान निधि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। रीवा क्षेत्र की बांड़ सागर परियोजना के शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष 30 हजार करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा।

किसानों का ब्याज भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के वादे तो किए परंतु कर्जमाफ नहीं किया और किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी लाद दी। हमारी सरकार किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतारेगी। सरकार किसानों से 20 रुपए किलो में गेहूं खरीदती है और गरीब परिवारों को एक रुपए किलो में देती है। केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन का वितरण भी किया जा रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। किसानों को गेहूं की कमी न आए इसके लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

गेहूं खरीदी के टारगेट से पिछड़े कई जिले इसलिए बढ़ाई तारीख

-प्रदेश के 37 जिलों में अब 31 मई तक खरीदी की जाएगी

भोपाल। मप्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 दिन आगे बढ़ा दी गई है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 37 जिलों में अब 31 मई तक खरीदी की जाएगी। पहले 16 मई तक खरीदी की जाना थी, लेकिन कई जिलों के टारगेट से पीछे रहने के कारण डेट बढ़ा दी गई। भोपाल टारगेट से काफी पीछे है। यहां अब तक 23 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा गया है, जबकि टारगेट 30 लाख क्विंटल का है। भोपाल में अब तक 23 हजार 504 किसान गेहूं बेच चुके हैं, जबकि 32 हजार 265 किसानों ने स्लॉट बुक करवाए हैं। यानी अभी 9 हजार किसान गेहूं बेचने से रह गए हैं। ऐसे में 30 लाख क्विंटल का टारगेट पूरा होने की संभावना है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया ने बताया, भोपाल के 77 सेंटरों पर गेहूं की खरीदी हो रही है। वहीं, 99 प्रतिशत गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। भोपाल संभाग के विदिशा, रायसेन, राजगढ़ एवं सीहोर में 755 सेंटरों पर 164 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा है। विदिशा और सीहोर में सबसे ज्यादा खरीदी की गई। ये जिले भी टारगेट से पीछे है, लेकिन 15 दिन में टारगेट पूरा होने का दावा अफसर कर रहे हैं।

स्वीकृत पदों के विपरीत 30 फीसदी अधिकारी-कर्मचारियों की दरकार

मध्यप्रदेश में अमले की कमी से जूझ रहा पशु पालन विभाग

भोपाल। विशेष संवाददाता

गौ संरक्षण व संवर्धन मप्र सरकार की प्राथमिकता में भले ही शामिल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी संभाल रही संस्था अमले की कमी से जूझ रही है। लिहाजा इसका खामियाजा न केवल पशु और पशुपालकों को बल्कि पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यबोझ के रूप में उठाना पड़ रहा है।

वजह यह भी है कि यहां पदस्थ अमले को रिक्त पड़े 30 प्रतिशत पदों का कार्य का दायित्व संभालना पड़ रह है। प्रदेश के पशुपालन विभाग में एडिशनल डारेक्टर से लेकर सहायक पशु चिकित्सकों के करीब 3692 से अधिक पद रिक्त हैं। इनका काम यहां पदस्थ 8451 लोगों को संभालना पड़ रहा है। क्योंकि विभागीय अधिकारियों की मानें तो विभाग में विभिन्न पदों के कुल 12143 पद हैं। इनमें सबसे ज्यादा सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं। 5795 पदों के विरुद्ध इनमें 3238 ही भरे हैं। इसके इतर विभाग को लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्वीकृत 849 लिपिक वर्गीय पदों का जिम्मा जहां 590 कर्मचारी संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत 2919 पदों के मुकाबले मात्र 2673 कर्मचारी ही मौजूदा समय में कार्यरत हैं।

अगस्त तक मिलेंगे 123 डॉक्टर

अधिकारी-कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभाग के पटरी पर लाने के लिये पशुपालन विभाग प्रबंधन जुट गया है। इसमें चिकित्सकों की पूर्ति अहम है। बताया जाता है कि इस तारतम्य में 123 पदों में अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संभावना जताई जाती है कि दिसंबर अंत तक 194 पदों को भी भर लिया जाएगा।

चिकित्सकों पर बढ़ा दबाव

अमले की कमी के कारण बताया जाता है कि पदस्थ डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ गया है। क्योंकि मैदानी अमले की पहले से कमी है। बावजूद इसके इनको नियमित कार्य के इतर सरकार के दूसरे तमाम आदेशों और योजनाओं का भी पालन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ज्यादा काम करने के बाद भी व्यवस्थाएं सामान्यतौर पर बहाल नहीं कर पा रहे हैं।

अमले की पूर्ति के लिए संचालनालय और सरकार सतत प्रयास कर रहे हैं। हम न केवल चिकित्सक और सहायक चिकित्सकों के बल्कि चतुर्थ श्रेणी के 694 पद भरने की तैयारी में हैं।

डॉ. आरके महिया, संचालक, पशु संचालनालय

भारत मक्का शिखर सम्मेलन-2022: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा

सरकार ने आठ साल में 43 फीसदी बढ़ाई मक्के की एमएसपी

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददाता

कई तरह के खाद्य पदार्थों के साथ ही मक्के का इस्तेमाल कुक्कट पालन और एथेनॉल उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में होने से न केवल भारत में, बल्कि विश्व में भी मक्का की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत मक्का शिखर सम्मेलन-2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार फसलों के विविधीकरण कार्यक्रम के तहत, विभिन्न पहलों के जरिये किसानों को मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही, सरकार ने विभिन्न पहल व पैकेजों से उद्यमियों को भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 8 साल के दौरान मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 43 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके साथ ही मक्का का उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी इसका काफी लाभ मिला है।

घरेलू स्तर पर मक्का की मांग उत्पादन के मुकाबले तेजी से बढ़ रही

मक्के को मिलेगा भरपूर समर्थन

देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन-2022 के 8वें संस्करण का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर थे। उन्होंने मक्का क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के भरपूर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कृषि हमारे देश की रीढ़ के समान है, जिसने कोविड-19 सहित हर संकट में देश की मदद की है। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि भी उत्साहवर्धक रही है, जिसका आंकड़ा चार लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

मप्र भी मक्का उत्पादक

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में भी मक्के की खेती होती है। मक्का दुनिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। मक्के की रोटी और भुट्टे के अलावा पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, कॉर्न फ्लेक्स के रूपों में दुनिया का पेट भरता है। मक्के का इस्तेमाल जहां इंसान करते है। वहीं इससे पशुओं के लिए चारा, और मुर्गियों और सूकरों के लिए दाना बनाया जाता है।

सीएम शिवराज सिंह ने प्राकृतिक खेती पर हुई कृषक संगोष्ठी को किया संबोधित

प्राकृतिक खेती धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान

- मुख्यमंत्री ने कहा- केमिस्ट्री लेब से प्रकृति लेब में ले जाने वाली प्राकृतिक खेती
- प्राकृतिक खेती से पैदा हुई सामग्री की संपूर्ण विश्व में मांग
- प्राकृतिक खेती से उपजी फल, सब्जी-अनाज में पौष्टिकता
- प्राकृतिक खेती का किसानों को भी मिलते हैं अच्छे दाम

भोपाल। संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान है। यह केमिस्ट्री लेब से निकलकर प्रकृति लेब में ले जाने वाली खेती है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली केमिकल रहित खेती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से धरती का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। किसानों के केंचुए जैसे उपयोगी कीट मित्र समाप्त होते जा रहे हैं। धरती की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले गेहूँ, धान, अनाज, फल, सब्जी आदि मनुष्यों में गंभीर रोग विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए शुरू किए गए अभियान के लिए हम सब उनके आभारी हैं। मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती पर सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में हुई कृषक संगोष्ठी को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव कृषि तथा किसान-कल्याण अजीत केसरी भी उपस्थित थे। नसरूल्लागंज कार्यक्रम में गुजरात के नीलकंठ धाम पोइचा के केवल स्वरूप स्वामी विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 17 जिलों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक संगोष्ठियां की जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए कार्यक्रम किए गए हैं।

रसायन के उपयोग से हो रहा कैंसर

मुख्यमंत्री ने कहा की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। कैंसर जैसी बीमारियों के होने का एक बड़ा कारण हानिकारक रसायनों का शरीर में प्रवेश करना है। रसायन और कीटनाशक के बढ़ते उपयोग से जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। आने वाली पीढ़ी को बेहतर धरती और पर्यावरण सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। यह प्राकृतिक खेती से ही संभव होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय हैं। प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी नहीं घटता है। जीवामृत, घन जीवामृत दोषरहित हैं, इनके उपयोग से गेहूं, धान, अनाज, फल, सब्जी की पौष्टिकता और स्वाद बढ़ता हैं। प्राकृतिक खेती से पैदा हुई सामग्री की सम्पूर्ण विश्व में बहुत अधिक मांग है, परिणामस्वरूप इससे उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि से किसान को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है।

मैं खुद करूंगा प्राकृतिक खेती

मुख्यमंत्री ने सभी किसानों से अपने खेत के एक भाग में प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इस खरीफ फसल से पांच एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से फसल लेना आरंभ करेंगे। नसरूल्लागंज में हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि गुरूप्रसाद शर्मा, रवि मालवीय तथा गांधी नगर अहमदाबाद से आए उप संचालक कृषि पीबी खिस्तारिया उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती जीरो बजट की खेती

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती जीरो बजट की खेती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं होने से प्राकृतिक खेती में लागत कम और आय अधिक हैं। इस खेती में किसी भी कृत्रिम तत्व का उपयोग नहीं होता। परिणामस्वरूप मिट्टी का संतुलन ठीक रहता है और मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है। अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होने से बिजली का उपयोग भी कम होता है। प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर और गौ-मूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों को गाय की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार प्रतिमाह 900 रुपए उपलब्ध कराएगी।

खरीफ बोवनी से पहले किसानों को मिली बड़ी राहत

सरकार ने बढ़ाई डीएपी पर 2501 प्रति बोरी सब्सिडी

भोपाल। संवाददाता

किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने खरीफ की बुवाई के इस सीजन में डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। सरकार ने इस पहले रबी सीजन में सब्सिडी बढ़ाई थी। अक्टूबर 2021 को सरकार ने रबी सत्र 2021-22 में 1650 प्रति बैग सब्सिडी बढ़ाई थी, इससे पहले साल 2020-21 में सब्सिडी 512 रुपए प्रति बोरी थी, जिसे पांच गुना बढ़ाकर 2501 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल के बजट जोकि 57,150 करोड़ रुपए था को बढ़ाकर खरीफ सीजन के लिए 60,939 रुपए करने का फैसला लिया है। खरीफ सीजन में धान जैसी फसलों के लिए उर्वरकों की जरूरत होती है। अप्रैल में हुए खरीफ सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न का राष्ट्रीय लक्ष्य चालू वर्ष के दौरान 3160 लाख टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है। दलहन और तिलहन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न का राष्ट्रीय लक्ष्य क्रमशः 295.5 लाख टन व 413.4 लाख टन निर्धारित किया गया है। पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 के 115.3 लाख टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 205.0 लाख टन कर दिया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री की सरकार ने डीएपी पर भी प्रति बैग सब्सिडी को बढ़ाकर 2,501 रुपए कर दिया है जो कि रबी सीजन 2021-22 में 1,650 रुपए प्रति बैग और वर्ष 2020-21 में 512 रुपए थी। भारतीय रसायनों के निर्यात ने वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रसायनों के भारतीय निर्यात ने रिकॉर्ड 29296 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लिया, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में रसायनों का भारतीय निर्यात 14210 मिलियन डॉलर का रहा था।

दावों की खुली पोल: 20वीं पशुधन गणना के आधार पर पशुधओं की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

» देशी नस्ल की गायों की संख्या में 5.5 फीसदी आई गिरावट

» सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने चला रहीं योजनाएं

देश में घटा देशी गाय का कुनबा

-हरियाणा नहीं अब देश में सबसे अधिक है गिर नस्ल की गाय

भोपाल/नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में एनबीएजीआर (राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी/विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया है। पिछले छह वर्षों में देश में देशी नस्ल की गायों की संख्या में 5.5 फीसदी गिरावट आयी है। 2013 में हुए 19वें पशुधन सर्वे में देश में 79 प्रतिशत देशी नस्लें थीं। 2019 के 20वें पशुधन सर्वे में देसी नस्ल की गाय 73.5 प्रतिशत रह गईं। पशुधन में गाय ही घटी हैं। 19वें सर्वे में गाय 37.3 फीसदी थीं, जो 20वें सर्वे में 36 फीसदी पर आ गया। जबकि विदेशी और संकर नस्ल की गायों की संख्या में इजाफा हुआ है। जर्सी, संकर जर्सी और एचएफ जैसी गायों की संख्या 2013 में कुल गोवंश का 21 प्रतिशत थी, जो 20वीं पशुगणना के हिसाब से 2019 में 26.5 फीसदी हो गया है। गायों की शीर्ष दस नस्लों की बात करें 20वीं पशुगणना के हिसाब से देश में पहले नंबर पर गिर गाय है, जबकि 19वीं पशुगणना के हिसाब से से देश में पहले नंबर पर हरियाणा नस्ल की गाय थीं।

पहले नंबर पर गिर गाय

पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट के अनुसार देश में देशी गायों में सबसे अधिक संख्या गिर की हैं। पहले नंबर पर गिर (68,57,784), जिसकी 4.8 फीसदी हिस्सेदारी, दूसरे नंबर पर लखीमी (68,29,484), जिसकी हिस्सेदारी 4.8 प्रतिशत, तीसरे नंबर पर साहीवाल (59,49,674), जिसकी हिस्सेदारी 4.2 प्रतिशत, चौथे नंबर पर बचौर (43,45,940), जिसकी हिस्सेदारी 3.1 प्रतिशत, पांचवें नंबर पर हरियाणा (27,57,186), जिसकी हिस्सेदारी 1.9 फीसदी है।

पहले नंबर पर बरकरार मुर्रा

देश में भैंसों की देसी नस्लों में 2.03 फीसदी की कमी आयी है, जबकि अवर्गीकृत नस्लों में 2.03 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2013 में देशी नस्लों की संख्या 6,15,59,809 थी, जबकि अवर्गीकृत नस्लों की संख्या 4,71,42,313 थी। वहीं पर अब 2019 में भैंस की देशी नस्लों की संख्या 6,00,04,846 और अवर्गीकृत नस्लों की संख्या 4,98,46,832 है। नस्ल वार भैंसों की संख्या की बात करें तो पहले नंबर पर मुर्रा बरकरार है 4,70,65,448, जिसकी हिस्सेदारी 42.8 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर मेहसाना (43,78,788) जिसकी हिस्सेदारी 4 फीसदी, तीसरे नंबर पर सुर्ती (24,52,362) जिसकी हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत, चौथे नंबर पर जाफराबादी (21,39,127) जिसकी हिस्सेदारी 1.9 फीसदी, पांचवें नंबर पर भदावरी (19,81,852) जिसकी हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत है।

देशी गायों की संख्या 14.21 करोड़

असम की लखीमी नस्ल की गाय दूसरे पायदान पर है, जबकि पिछले सर्वे के 37 नस्लों में वह शामिल ही नहीं थी। नए सर्वे में कुल गौधन में लखीमी गाय की भागीदारी 4.8 फीसदी है। बिहार और झारखंड में पाई जाने वाली बच्चौर नस्ल की गायों की संख्या करीब तीन गुना बढ़ी है। इनमें से 77 फीसदी झारखंड और 23 फीसदी बिहार में हैं। अन्य नस्लों जैसे कि कांकरेज और कोसली का भी कुल स्वदेशी मवेशियों में से प्रत्येक का 1 प्रतिशत से अधिक योगदान है। अन्य सभी मान्यता प्राप्त नस्लें मिलकर कुल मवेशी आबादी का 8.1 फीसदी योगदान करती हैं। देश में देशी गायों की संख्या 14,21,06,466 है।

14 देशी नस्लों में वृद्धि

सबसे कम संख्या वाली गायों की बात करें तो बेलाही नस्ल की गायों की संख्या सबसे कम 5,264 है। दूसरे नंबर पर पुंगनूर (13,275) तीसरे नंबर पर पलीकुलम (13,934) चौथे पर वेचुर (15181) और पांचवें नंबर पर मेवाती (15,181) है। 14 देशी नस्लों में वृद्धि दर्ज की गई है। वेचुर (512 फीसदी), पुंगनूर, (369 फीसदी), बरगुर (240 फीसदी), बचौर (181 फीसदी), कृष्णा घाटी (57 फीसदी), पुलिकुलम, (38 फीसदी), सिरी (36 फीसदी), गिर (34.12 फीसदी), अमृतमहल (31 फीसदी), साहीवाल (22 फीसदी), ओंगोल (11 फीसदी), लाल सिंधी (10 फीसदी), (6 फीसदी) और पोनवार (2.46 फीसदी) नस्ल में वृद्धि दर्ज की गई है।

भेड़ों की नेल्लोर नस्ल में इजाफा

भेड़ में 3 विदेशी और 26 देशी नस्लें पाई गईं। शुद्ध विदेशी नस्लों में कोरिडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से 17.3 प्रतिशत है। स्वदेशी नस्लों में नेल्लोर नस्ल का योगदान 20.0 प्रतिशत के साथ अधिक है। स्वदेशी में सबसे अधिक संख्या नेल्लोर नस्ल की है 1,40,43,835, जो 20 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर बेल्लारी नस्ल (42,75,218) है, जो 6.1 प्रतिशत है। तीसरे नंबर पर मारवाड़ी नस्ल है (28,70,057), जो 4.1 प्रतिशत, चौथे नंबर पर डेक्कानी नस्ल (23,83,932) है, जो 3.4 प्रतिशत है। पांचवें नंबर पर केंगुरी नस्ल (12,86,284) जो 1.8 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में यह खास

रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि 4 विदेशी/संकर नस्लें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशु का योगदान लगभग 26.5 प्रतिशत है जबकि 73.5 प्रतिशत स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी हैं। कुल विदेशी/संकर मवेशियों में संकर होल्स्टीन फाइजियन (एचएफ) के 39.3 प्रतिशत की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा 49.3 प्रतिशत है। कुल देशी मवेशियों में गिर, लखीमी और साहीवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है। भैंस में मुर्रा नस्ल का प्रमुख योगदान 42.8 प्रतिशत है, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है।

भेड़ में तीन विदेशी और 26 देशी नस्ल

भेड़ में 3 विदेशी और 26 देशी नस्लें पाई गईं। शुद्ध विदेशी नस्लों में कोरिडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से 17.3 प्रतिशत है। स्वदेशी नस्लों में नेल्लोर नस्ल का योगदान 20.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ श्रेणी में सबसे अधिक है। देश में बकरियों की 28 देशी नस्लें पाई गई हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान 18.6 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है। विदेशी/संकर सूअरों में संकर नस्ल के सूअर का योगदान 86.6 प्रतिशत है, जबकि यॉर्कशायर का योगदान 8.4 प्रतिशत है। स्वदेशी सूअरों में डूम नस्ल का योगदान 3.9 प्रतिशत है। घोड़ा तथा टट्टुओं में मारवाड़ी नस्ल का हिस्सा प्रमुख रूप से 9.8 प्रतिशत है। गधों में स्पीति नस्ल की हिस्सेदारी 8.3 प्रतिशत है। ऊंट में बीकानेरी नस्ल का योगदान 29.6 प्रतिशत है। कुक्कुट, देसी मुर्गी में, असील नस्ल मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट पालन और वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म दोनों में योगदान करती है।

पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और समन्वय में कछुए की भूमिका

डॉ. माधवी धैर्यकर, डॉ. शोभा जावरे
एसडब्ल्यू एफएच, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर

एशिया के कई क्षेत्रों में कछुओं की आबादी का विलोपन कछुओं के लिए भोजन, पारंपरिक चिकित्सा, या पालतू जानवरों की बढ़ती मांग से प्रेरित है, जिसके परिणामस्वरूप जंगली कछुए की आबादी का अभूतपूर्व व्यापार और तस्करी हुई है। स्वस्थ महासागरों को समुद्री कछुओं की आवश्यकता होती है। समुद्री कछुए एक कीस्टोन प्रजाति हैं, यदि एक कीस्टोन प्रजाति को एक आवास से हटा दिया जाता है, तो प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो सकती है, जो अन्य वन्यजीवों और जीवों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है।

कछुओं की समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और गतिशीलता के विकास और रखरखाव में कई मान्यता प्राप्त भूमिकाएं हैं- वे शिकार, उपभोक्ता, प्रतियोगी और मेजबान के रूप में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अंत:क्रियात्मक अंत:क्रियाओं का एक अभिन्न अंग हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र के भीतर और बीच में पोषक तत्व और ऊर्जा हस्तांतरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी काम करते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की भौतिक संरचना को भी काफी हद तक संशोधित कर सकता है। समुद्री कछुए खाद्य जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और दुनिया के महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कई अन्य जीवों को केवल खाने के द्वारा नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, हरे कछुए मुख्य रूप से समुद्री घास खाते हैं। समुद्री घास के मैदानों पर चरने से, वे घास को बहुत लंबे समय तक बढ़ने से रोकते हैं और खुद का दम घुटता है।

नॉर्दन रिवर टेरापिन
IUCN की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त, CITES : परिशिष्ट-I, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अनुसूची-1, 19वीं और 20वीं सदी में कलकत्ता के बाजारों में आपूर्ति सहित स्थानीय जीवन निर्वाह और कर्मकांडी उपभोग के साथ-साथ कुछ क्षेत्रीय व्यापार के लिये इनका दुरूपयोग किया गया।

रेड-क्राउन रूफ टर्टल
ऐतिहासिक रूप से यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा नदी में पाई जाती थी। यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी वाला एकमात्र क्षेत्र है।
IUCN की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त, CITES: परिशिष्ट-II, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I, प्रदूषण और बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों जैसे- मानव उपभोग और सिंचाई के लिए जल की निकासी तथा अपस्ट्रीम बांधों एवं जलाशयों से अनियमित प्रवाह के कारण आवास की हानि या गिरावट होती है।

ब्लैक सॉफ्टशेल कछुआ
वे पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के तालाबों में पाए जाते हैं। इसकी वितरण सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां भी शामिल हैं। IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त, CITES : परिशिष्ट- ढ्ढ, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: कोई कानूनी संरक्षण नहीं, कछुए के मांस और अंडे का सेवन, रेत खनन, आर्द्रभूमि का अतिक्रमण एवं बाढ़ के पैटर्न में बदलाव।

अच्छे और स्वस्थ समुद्री घास के बिस्तर फिर से तथाकथित पारिस्थितिक तंत्र कार्यों की एक भीड़ का प्रदर्शन करते हैं। वे कई समुद्री प्रजातियों के लिए एक नर्सरी ग्राउंड हैं और इसके अतिरिक्त समुद्र में एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक और ऑक्सीजन प्रदाता हैं। कछुए अपने शिकार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, लेदरबैक समुद्र में जेलीफिश की मात्रा का प्रबंधन करने में मदद करते हैं, हॉक्सबिल अंतरिक्ष के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले स्पंज खाकर रीफ़ की मदद करते हैं। कछुओं का घोंसला समुद्र तटों की मदद करता है। अंडे और हैचलिंग द्वारा छोड़े गए पोषक तत्व जो जीवित नहीं रहते हैं, तटीय वनस्पति के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। कई जानवरों के लिए हैचलिंग भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पक्षी, मछली, स्तनधारी जैसे रैकून और अन्य घोंसले के मौसम के दौरान जीवित रहने के लिए प्रचुर मात्रा में हैचलिंग पर भरोसा करते हैं। वे तटीय अर्थव्यवस्थाओं और देशी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्री घास पर चरने वाले हरे कछुए समुद्री घास के बिस्तरों को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और स्वस्थ समुद्री घास कई प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है और कार्बन का भंडारण करती है। समुद्री कछुओं का भी पानी से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घोंसले के शिकार समुद्री कछुए अपने अंडे रेत में जमा करके समुद्र तटों की मदद करते हैं। पीछे छोड़े गए अंडे के छिलके और बिना पके अंडे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो समुद्र तट घास जैसे किनारे पर बालू का टीला वनस्पति को पोषण देते हैं, जो टीला को स्थिर करते हैं और तटीय क्षरण को रोकने में मदद करते हैं। समुद्री कछुए जीवन के सभी चरणों में अन्य जानवरों के शिकार होते हैं। टर्टल सर्वाइवल एलायंस (टीएसए) भारत गैर-समुद्री चीलोनियन, मगरमच्छ और सीतासियों के संरक्षण के लिए समर्पित है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में देश भर में पांच क्षेत्र-आधारित परियोजनाओं के माध्यम से डब्ल्यूसीएस-इंडिया के एक क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। हाल ही में भारतीय जीवविज्ञानी शैलेंद्र सिंह को तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए की प्रजातियों को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने हेतु बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश में मीठे पानी के कछुओं और अन्य प्रकार के कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं।

बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार: वर्ष 2006 में स्थापित यह पुरस्कार कछुओं के संरक्षण एवं जैविकी तथा चेलोनियन कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी कम्युनिटी में नेतृत्व क्षमता को सम्मानित करने हेतु दिया जाने वाला एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे कछुआ संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 'बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार' कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे 'टर्टल सर्वाइवल एलायंस कच्छप और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह, कछुआ संरक्षण तथा 'कछुआ संरक्षण कोष' द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं को देश के विभिन्न हिस्सों में टीएसए इंडिया के अनुसंधान, संरक्षण प्रजनन और शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। सुंदरबन में नॉर्दन रिवर टेरापिन को संरक्षित किया जा रहा है। सुंदरबन पारिस्थितिकी क्षेत्र उनका प्राकृतिक आवास है। चंबल में रेड-क्राउन रूफ टर्टल (बाटागुर बास्का)। असम के विभिन्न मंदिरों में ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल (निल्सोनिया नाइग्रिकन्स)। समुद्री कछुए , टेरेपिन (ताजे जल के कछुए) और अन्य कछुओं की तुलना में आकार में बड़े होते हैं।

पशु पालन का दुग्ध उत्पादन में योगदान

डॉ. भावना अहरवाल, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन विभाग, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर

दुग्ध उत्पादन स्तनधारी पशुधन का प्रयोग दूध के रूप में होता है, जिसे आसानी से संसाधित करके अल्प दुग्ध उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि दही, पनीर, मख्खन, आईसक्रीम, लस्सी, खोया व मिठाइयां। पशुधन का प्रयोग इस प्रकार से किए जाने से प्राप्त भोजन व ऊर्जा उन्हें मारकर खाने की बजाय कई गुणा अधिक होती है। पशुधन को मारकर उनके मांस से प्रोटीन व ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

अंडों से भी प्रोटीन व ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गोबर की खाद का प्रयोग खेतों में डालकर फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किया जाता हैं। पशुओं के रक्त व हड्डियों का प्रयोग भी खाद के रूप में किया जाता है। एक बैल से हर रोज लगभग 20 किलो गोबर मिलता है। इस गोबर में 35 गुणा पत्तियां, कूड़ा-करकट, खेत में बचे हुए डंठल आदि तथा 20 गुणा मिट्टी डालकर कम्पोस्ट खाद तैयार की जाए तो एक बैल से 300 टन खाद प्राप्त होती है, जिसमें 10 टन एनपी होता है, जो नमी वाली 145 एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है तथा जिससे 40 प्रतिशत कृषि उत्पाद बढ़ता है व गृह एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पशु खेतों में कई प्रकार के कार्य जैसे खेती में उपयुक्त उपकरणों को खींचना, कुंए से खेतों के लिए पानी निकालना, जंगलों से लकड़ी उठाना आदि कार्य करते हैं। आज के मशीनीयुग में पशु शक्ति कई विकाशील देशों में अक्षय ऊर्जा का स्त्रोत है। पशुधन हमें हमारे सुख के लिए यातायात व ऊर्जा के साधन हमें देते हैं। गधे, घोड़े, बैल, ऊंट तथा याक जैसे पशुओं का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा के लिए किया जाता है। भाप की शक्ति पहले पशुधन गैर-मानव श्रम का एकमात्र उपलब्ध साधन था। इस उद्देश्य के लिए के लिए पशुओं का उपयोग आज भी किया जाता है। पशुओं का उपयोग आज भी किया जाता है। पशुओं का उपयोग खेत जोतने के लिए, सामान ढुलाई के लिए और सेना में किया जाता है। अच्छे पशुओं का स्वामी बनकर हम समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने पशुओं की देखभाल सही नहीं करते हैं तो हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी कम करते हैं। पशुओं की चराई को कभी-कभी खरपतवार तथा झाड़ियों के नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उन क्षेत्रों में जहां जंगल में आग लगती है। बकरियों तथा भेड़ों का प्रयोग सूखी पत्तियों का खाने के लिए किया जाता है जिससे जलने योग्य सामग्री कम हो जाती है। आग का खतरा भी कम हो। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के बाद बकरियों, भेड़ों और गायों की ऐसी नई नस्लें तैयार की है, जो अपने दूध के साथ मानवोपयोगी तत्व भी दूध में प्रदान करती हैं, जिससे दवा निर्माण क्षेत्र में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। क्योंकि इससे कुछ दुर्लभ दवाओं के उत्पादन मूल्यों में काफी कमी आएगी। पशुधन भेड़-बकरी से ऊन व मौहेर प्राप्त होती है, जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। पशुओं के चमड़े से जूते, पर्स, जैकेट इत्यादि बनाए जाते हैं। खेती के साथ-साथ पशु पालन लगभग 70 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। पशुओं के सींग तथा हड्डियां कारखानों में अस्थिचूर्ण तथा अन्य उत्पाद बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अस्थिचूर्ण को खनिज पूरक के रूप में पशु आहार में मिलाया जाता है और खाद के रूप भी प्रयोग होता है। कोई भी कार्य करने से पहले हम यह सोचते हैं कि क्या कार्य किया जाए। यदि हम ऐसे ही कार्य का चुनाव कर लेते हैं तो उसमें हमें यह सोचना चाहिए कि यह कार्य क्यों, कैसे व कहां करें, एक सही सोच, सही कार्य प्रणाली व सही जगह पर हम अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं को सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के कारण यदि पशु बीमार होता है तो इससे पशु का उपचार करवाने में पशुपालकों को आर्थिक हानि होने के साथ-साथ बीमार पशु कमजोर भी हो जाता है। इससे पशु के दूध देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है व कई बार पशु दूध देना भी बंद कर देता है। कई बार बीमारी बढ़ने पर पशु की मौत भी हो जाती है। ऐसे में शैड के तापमान का खास ध्यान रखें। भैंस जाति के पशु सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि पशु को ठंड लगने का अंदेशा हो तो ऐसे में पशु पालक सर्द हवाओं से बचाएं, सर्द हवाओं से बचाने के लिए शैड के लिए रोशनदान, दरवाजों व खिड़कियों को टाट और बोरे से ढंक दें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि शैड बिल्कुल भी पैक न हो अर्थात शेड में थोड़ी-बहुत ताजी हवा भी आनी चाहिए। इसके लिए पल्ली या तिरपाल के नीचले हिस्से को थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए। इसी प्रकार पल्ली या तिरपाल के ऊपरी हिस्से को थोड़ा नीचे खिसका देना चाहिए। ऐसा करने से नीचले हिस्से से ताजी हवा अंदर आएगी,जो गर्म होने के उपरांत ऊपरी खुले हिस्से से बाहर निकल जाएगी। ऐसा करने से श्वास संबन्धी रोग होने की संभावना कम रहेगी।

विश्व मधुमक्खी दिवस पर विशेष

मधुमक्खी पालकों के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा समाधान

बैंगलुरु स्थित आईआईएचआर के वैज्ञानिकों पॉलीहाउस में खेती करने वाले किसानों की एक बड़ी चुनौती का ढूंढा समाधान। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारतीय नस्ल वाली मधुमक्खी 'एपिस सेराना' और डंक रहित मधुमक्खी 'टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस' को यदि पॉलीहाउस में पाला जाए तो वहां के माहौल में भी खुले खेतों जैसी कीट-पतंगों वाली पॉलीनेशन की खूबियां और फायदे हासिल हो सकते हैं। इस नयी तकनीक से पॉलीहाउस की खेती की लागत घटती है और कमाई बढ़ती है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर विशेष- पॉलीहाउस की खेती के भले ही ढेरों फ़ायदे हों लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं होतीं। मसलन, पॉलीहाउस की खेती में फलों और सब्ज़ियों की अच्छी उपज पाने के लिए हाथ से परागण करवाना पड़ता है। क्योंकि पॉलीहाउस के संरक्षित माहौल से कीट-पतंगों को बाहर रखा जाता है। हाथों से पॉलीनेशन करवाने का तरीका एक मुश्किल और मेहनतकश काम है। इससे फ़सल की लागत भी बढ़ती है। जबकि खुले खेतों में उन्मुक्त कीट-पतंगे फलों और सब्जियों के बीच परागण की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। इसीलिए पॉलीहाउस में ऐसे कीट-पतंगों की कमी अखरती है जो खुले खेतों की तरह बंद माहौल में भी किसानों को कुदरती परागण की सौगात दे सकें। किसानों की इसी जरूरत को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बैंगलुरु स्थित संस्थान आईआईएचआर को पॉलीहाउस में होने वाली पॉलीनेशन की चुनौती का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 2019-20 के दौरान आईआईएचआर के वैज्ञानिकों ने तीन फसल चक्रों का गहन अध्ययन करके अनेक प्रयोग किए। फिर उन्होंने तय किया कि पॉलीहाउस में यदि भारतीय नस्ल वाली मधुमक्खी 'एपिस सेराना' और डंक रहित मधुमक्खी 'टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस' को पाला जाए तो वहां के जीवाणु सुरक्षित माहौल में भी खुले खेतों जैसी कीट-पतंगों वाली पॉलीनेशन की खूबियां और फायदे हासिल हो सकते हैं। अपने प्रयोग के दौरान आईआईएचआर के बागवानी विज्ञानियों ने पाया कि खरबूजे और खीरे के नर और मादा फूलों पर दोनों प्रजातियों की कार्यकर्ता मधुमक्खियों ने खूब दौरे किए। इससे फूलों के पॉलीनेशन की प्रक्रिया बखूबी सम्पन्न हुई।

जबलपुर में जापानी आम की पिछले साल 21 हजार रुपए नग लगी बोली

जापानी आम की पैदावार ने उम्मीदों पर फेरा पानी

जबलपुर। संवाददाता

जबलपुर यूं ही मशहूर नहीं है। यह नर्मदा नदी और संगमरमरी वादियों के लिए देश-विदेश में विख्यात है तो इसे मदनमहल की पहाड़ी और 52 ताल-तलैयों के लिए भी जाना जाता है। इन बातों की जानकारी तो हमें इतिहास के पन्नों में झांकते ही पढ़ने मिल जाती है, लेकिन शायद ही आप लोगों को यह पता हो कि जबलपुर दुनिया के सबसे महंगे आम पैदा करने के लिए भी जाना जाता है। जापान में मिलने वाले सबसे महंगे आम जबलपुर में भी पैदा हो रहे हैं। नर्मदा किनारे बसे शहर से लगे ग्राम डगडगा हिनौता के एक बगीचे में इन दिनों जापानी के सबसे महंगे आम श्ताइयो नो तमागोश और मियाजाकी जैसे आम शहर की इस बगिया में भी हो रहे हैं। पिछले साल भी इन आमों की मांग सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि मुंबई तक रही। वहां के कई आम कारोबारी इस आम के लिए 21 हजार रुपए प्रति नग तक की बोली लगाई थी। यहां पर हो रहे एक आम का वजन करीब 900 ग्राम तक होता है। हालांकि बगीचे के मालिक संकल्प सिंह परिहार ने इस सीजन में भी आम बेचने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार आम की फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं है। महंगा दाम मिलने के बाद भी इस बार वह यह आम नहीं बेचेंगे।

डायनासोर के अंडे की तरह आम

दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम मियाजाकी है। इस आम की खेती जापान के शहर मियाजाकी में की जाती है। इस वजह से इसका नाम भी यही रखा गया है। यहां पर स्थानीय भाषा में मियाजाकी को टाइयो नो तमागो कहा जाता है। इस आम का रंग हरा और पीला नहीं होता है, बल्कि इसका रंग लाल होता है और ये डायनासोर के अंडे की तरह होता है। बताते हैं कि मियाजाकी आम का वजन 350 से 900 ग्राम तक होता है। एक मियाजाकी आम में 15 फीसदी से अधिक चीनी होती है। यही वजह है कि इस आम की मिठास, दूसरे आमों की तुलना में अच्छी रहती है। इसी मांग की वजह से यह अधिक कीमत पर बिकता है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

आम की खेती करने वाले संकल्प ने बताते हैं कि उनका लक्ष्य अपने बगीचे में तइयो नो तमागो किस्म के 500 पेड़ तैयार करने का है। इसके बाद ही बाकी किस्म के आम की तरह वे इस किस्म के आम बाजार में बेचेंगे। उनके बगीचे में 6 विदेशी किस्मों के आम लगे हैं। फिलहाल वे 12 एकड़ में आम की खेती कर रहे हैं। हालांकि इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने बगीचे में चोरों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाठी लेकर कई सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, जो आमों की रखवाली करते हैं। वहीं आम के दो पेड़ों की रखवाली करने के लिए चार गार्ड और 6.6 कुत्तों के इंतजाम किए हैं।

20 लाख क्विंटल खरीदी का था लक्ष्य, महज 220 क्विंटल खरीदी

श्योपुर में समर्थन से किनारा सिर्फ पांच किसानों ने बेचा गेहूं

-डेढ़ महीने में मंडी में छह लाख क्विंटल गेंहू बेच चुके किसान

श्योपुर। संवाददाता

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए पिछले साल तक किसानों की भारी भीड़ उमड़ती रही हो, लेकिन इस बार जिले के किसानों ने समर्थन मूल्य की तरफ मुंह भी नहीं किया है। यही कारण है कि गेहूं खरीदी श्योपुर जिले में बनाए गए केन्द्रों पर डेढ़ माह की अवधि के दौरान सिर्फ 5 किसानों ने ही 220 क्विंटल गेहूं विक्रय किया, जबकि इस अवधि में जिले के किसान श्योपुर की मंडी में 6 लाख क्विंटल गेहूं विक्रय कर गए। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों के कम आने के कारण इस बार गेहूं खरीदा लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद कम दिख रही है। हालांकि सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक के आदेश से मंडी में गेहूं के दाम कम हुए हैं, इससे समर्थन मूल्य पर गेहूं की आवक बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मगर इसके बाद भी गेहूं खरीदने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा इसको लेकर संदेह है।

मंडी में उमड़ी भीड़- उधर, श्योपुर मंडी में डेढ़ माह की अवधि के दौरान गेहूं विक्रय के लिए किसानों की काफी भीड़ उमड़ी। क्योंकि मंडी में किसानों को गेहूं का भाव इस बार समर्थन मूल्य से अधिक मिला। मंडी प्रशासन का कहना है कि डेढ़ माह में

केंद्रों पर सन्नाटा

इस बार विभाग ने जिले में 20 लाख क्विंटल गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। गेहूं खरीदी के लिए श्योपुर जिले में 37 केन्द्र बनाए गए हैं, जहां 5 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू है। करीब डेढ़ माह बीतने के बाद भी खरीद केन्द्रों पर सन्नाटा ही पसरा रहा। इस अवधि के दौरान सिर्फ 5 किसान एक खरीद केन्द्र पर ही गेहूं विक्रय के लिए पहुंचे पाए। जबकि शेष खरीद केन्द्रों पर अभी तक कोई किसान गेंहू विक्रय करने के लिए पहुंचा ही नहीं।

पिछड़ने के कुछ कारण

- गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। जबकि मंडियों में किसानों को उपज के दाम 2200 रुपए क्विंटल तक मिले।
- समर्थन मूल्य के भाव खुलने के बाद किसानों ने खुले बाजार के भाव देखे। इस फेर में किसानों ने उपज रोकी और दाम बढ़े तो मंडियों में लेकर पहुंचे।
- इस बार गेहूं खरीदी के लिए सरकार के नियम थोड़े सख्त कर दिए हैं। इसके अलावा जिले में गेहूं का रकबा भी बीते साल की तुलना में घटा है।
- अबकी बार स्लॉट बुकिंग होने से किसान इस व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए। जटिलताओं में उलझने के बजाए उन्हें मंडियों में उपज बेचना आसान लगा।

फसल सिंचाई में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा

ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई शुरू, अच्छी पैदावार की उम्मीद

हरदा। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई शुरू हो चुकी है। जिसमें किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। लेकिन इस बार बिजली कटौती के कारण मूंग की फसल की सिंचाई में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

इस साल मूंग की उपज से किसानों ने ज्यादा उम्मीद लगाकर रखी थी। लेकिन अपेक्षाकृत नहर से पानी नहीं मिला एवं स्वयं के ट्यूबवेल वाले किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिली। जबकि नहर से सिंचाई करने वाले किसानों ने अब तक कटाई शुरू नहीं की है। पिछले साल जिले में नहर से पानी छोड़ने पर मूंग की सिंचाई से अच्छी पैदावार हुआ था। इसके साथ ही मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी। फसल कटाई करने वाले किसानों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम पैदावार हुई है।

इसका कारण मौसम के बदलाव को बताया जा रहा कि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में तापमान ज्यादा होने के कारण मूंग की फसल प्रभावित हुई है। इसका असर मूंग की पैदावार पर भी पड़ा है। किसानों ने बताया कि इस वर्ष मूंग की फसल की सिंचाई करने में बिजली कटौती का सामना ज्यादा करना पड़ा। इसके कारण पिछले साल से कम पैदावार हुई है। इसके साथ ही किसानों का मूंग का दाम भी मंडी में अच्छा मिल था।

चार क्विंटल प्रति एकड़

ग्राम कचबैडी के किसान कपिल जाट ने बताया कि गांव में मूंग की फसल की कटाई की जा रही है। अधिकतम चार क्विंटल प्रति एकड़ मूंग की पैदावार हुई है। उन्होंने बताया कि उनके 10 एकड़ खेत में 40 क्विंटल मूंग का उत्पादन हुआ। किसान पूनमचंद्र भूसारे ने बताया कि पिछले साल यह पैदावार करीब आठ क्विंटल प्रति एकड़ हुई थी। इसके साथ ही पिछले साल समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की गई थी। इसके कारण जिले की कृषि उपज मंडी में अच्छा भाव मिल गया था। इसलिए किसान इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की उम्मीद लगाए हुए हैं।

- जिले में मूंग की करीब 10 दिन से कटाई की जा रही है। इस बार भी अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हालांकि मूंग की कटाई करने वाले किसानों के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा कम पैदावार की जानकारी है। जिले में 1 लाख 36 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी की गई थी।

- एमपीएस चंद्रावत, उप संचालक, कृषि विभाग, हरदा

मंदिर के पास बनकर लगभग तैयार हो गया

उज्जैन में तैयार हुआ प्रदेश का पहला अमृत सरोवर

उज्जैन। प्रदेश का संभवत पहला अमृत सरोवर उज्जैन के चित्रगुप्त मंदिर के पास बनकर लगभग तैयार हो गया है। खोदाई में यहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा की मूर्तियां निकली हैं, जिन्हें फिलहाल मंदिर के पास ओटले पर रखा गया है। नगर निगम ने तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में संवारने के लिए योजना बनाई है। इसी कड़ी में एक टापू और कुछ रिचार्ज पीट बनाए जा रहे हैं। जल्द ही यहां पौधारोपण कर उद्यान भी बनाया जाएगा। तालाब में फव्वारे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजन के लिए बारिश का पानी अधिक से अधिक सहेजने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी अमृत सरोवर योजना को मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। उज्जैन

में इस दिशा में 100 से बड़े तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में एक तालाब का निर्माण रामजनार्दन मंदिर से कुछ आगे चित्रगुप्त मंदिर के पास नगर निगम के सहयोग से एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन इंडिया ने किया है। लगभग 20 हजार क्यूबिक मिट्टी निकाल तालाब बनाया गया है। कहा गया है कि इसमें 2 करोड़ लीटर पानी का संचय होगा। इससे निश्चित ही पशु-पक्षियों को पीने के लिए पानी तो मिलेगा ही आसपास का क्षेत्र सालभर हरा-भरा भी रहेगा। यहीं तालाब के बीच एक टापू बनाया जा रहा है और रिचार्ज पीट भी। काम देख यहां आने वाले लोग अच्छा महसूस करेंगे। वर्षाकाल में यहां निगम द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। बाद में फाउंटेशन भी लगाया जाएगा।

सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की 52वीं वार्षिक बैठक का समापन

सोया गंध के लिए जिम्मेदार एंजाइम से मुक्त होगी एनआरसी 150 किस्म

» दो दिनी बैठक में देशभर के 33 केंद्रों के 150 वैज्ञानिकों ने भाग लिया

इंदौर। संवाददाता

नगर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में ही विकसित सोयाबीन की किस्म एनआरसी 150 के उपयोग की अनुशंसा किस्म पहचान समिति ने की। दो दिवसीय अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की 52वीं वार्षिक बैठक के समापन सत्र में दो दिनी चर्चा के बाद उक्त अनुशंसा की गई। इसकी विशेषता यह है कि यह मात्र 91 दिन में परिपक्व होती है। यह सोया गंध के लिए जिम्मेदार लाइपोक्सीजिनेज-2 एंजाइम से मुक्त है। यह रोग प्रतिरोधी भी है।

बैठक के अंतिम सत्र में संस्थान की कार्यवाह निदेशक डॉ. नीता खांडेकर ने बताया कि किस्म पहचान समिति ने 6 सोयाबीन किस्मों के उपयोग के लिए अनुशंसा की है। यह देश के तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त होगी। किस्म वीएलएस 99 (उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए), एनआरसी 149 (उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए) और मध्य क्षेत्र के लिए 4 किस्में एनआरसी 152, एनआरसी 150, जेएस 21-72 एवं हिम्सो-1689 की पहचान की गई है। इस वर्ष सोयाबीन अनुसंधान संस्थान

वांछनीय लक्षणों से मुक्त

सोयाबीन किस्म एनआरसी 149 में उत्तरी मैदानी क्षेत्र के प्रमुख पीला मोक रोग, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के साथ-साथ गर्डल बीटल और पर्णभक्षी कीटों के लिए प्रतिरोधी है। एनआरसी 152 नामक किस्म अतिशीघ्र पकने वाली (90 दिनों से कम), खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त तथा अपौष्टिक क्लुनिट् ट्रिप्सिंग इनहिबिटर और लाइपोक्सीजेनेस एसिड-2 जैसे अवांछनीय लक्षणों से मुक्त है।

98 दिन में पककर तैयार

मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध जबलपुर केंद्र से विकसित सोयाबीन की एक अन्य किस्म जेएस 21-72 पीला मोक वायरस, चारकोल रोट, बैक्टीरियल पस्ट्यूल और लीफ स्पाट रोग के लिए प्रतिरोधी होने के साथ 98 दिन में पककर उत्पादन देने में सक्षम है। समापन सत्र सहायक महानिदेशक तिल एवं दलहन डॉ. संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। दो दिनी बैठक में देशभर के 33 केंद्रों के 150 वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

आईआईटी इंदौर ने की प्राकृतिक पौधों के कंपाउंड्स की पहचान

इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने क्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन को लक्षित करके सार्स- कोव-2 प्रतिकृति के विशिष्ट निषेध के लिए प्राकृतिक पौधों के कंपाउंड्स की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन बायोसाइंसेस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के इंफेक्शन बायो इंजीनियरिंग ग्रुप (आइबीईजी) के डॉ. हेमचंद्र झा और कम्प्यूटेशनल बायोफिजिक्स ग्रुप के डॉ. परिमल कर के नेतृत्व में विद्यार्थी धर्मेंद्र कश्यप और राजर्षि राय के साथ किया है। डॉ. हेमचंद्र झा ने बताया कि औषधीय पौधों का उपयोग पारंपरिक रूप से कई दर्शकों से विभिन्न रोगजनक रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता रहा है।

संस्थान के डॉ. हेमचंद्र झा और डॉ. परिमल कर ने किया शोध

पिछले अध्ययन में डॉ. हेमचंद्र झा और उनकी टीम ने स्पाइक, एन्वेलप और मेम्ब्रेन प्रोटीन में उच्च उत्परिवर्तन दर की सूचना दी थी। इस बीच क्लियोकैप्सिड एन प्रोटीन में म्युटेशन दर, प्रकोप के बाद से बहुत कम है इसलिए औषधीय पौधों के अर्क के माध्यम से उपचार के लिए एन प्रोटीन की संपत्ति को रोकना एक अनूठा तरीका हो सकता है। एन प्रोटीन में कम उत्परिवर्तन और विथेनोलाइड डी, हाइपरिसिन और सिलीमारिन के साथ उच्च बाध्यकारी आत्मीयता के कारण पहचाने गए यौगिक लंबी अवधि के लिए प्रभावी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से सिलीमारिन नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण में है और तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम को रोकने के लिए भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी के वित्तीय सहायता से पूरा किया गया। आईआईटी इंदौर के पीआरओ सुनिल कुमार का कहना है कि संस्थान के सभी संस्थानों में शोध कार्य होते रहते हैं। इसमें से कई शोध भारत सरकार के साथ किए जाते हैं। इसके पहले भी प्रोटीन पर विभिन्न तरह के शोध संस्थान के प्रोफेसर कर चुके हैं।

अभयारण्य में आने के कारण अपनी ही जमीन से मिट्टी नहीं उठा पा रहे किसान

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करैरा सोनचिरैया अभ्यारण क्षेत्र में निवास करने वाले 32 गांवों के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है। चिलचिलाती धूप में पैदल मार्च निकालकर किसान अनुविभागीय अधिकारी दिनेशचंद्र शुक्ला के कार्यालय पर पहुंचे। किसानों का कहना है कि वर्ष 1981 से लेकर आज तक अभ्यारण के अंतर्गत आने वाले 32 गांव की 202.2 वर्ग किलोमीटर भूमि सोन चिरैया संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दी गई है। इस कारण से वहां निवासरत किसान अपनी भूमि का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते। यहां तक कि अपने उपयोग के लिए अपने ही खेत में से मिट्टी भी नहीं उठा सकते। जबकि अभ्यारण की आड़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रतिदिन क्षेत्र से लाखों रुपये की रेत का अवैध उत्खनन नेता और उनके लोग कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में कई समस्याओं का जन्म हो रहा है। यदि इस क्षेत्र को अभ्यारण से शीघ्र मुक्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा।

महिला किसानों ने कराया मुंडन- ज्ञापन देने के पश्चात किसानों ने सोनचिरैया अभ्यारण से दु:खित होकर मुंडन कराया। इसमें महिला किसान कृष्णा देवी रावत, होतम सिंह रावत सहित अन्य आधा दर्जन किसानों ने अपना मुंडन तहसील कार्यालय के सामने ही सड़क पर करा कर विरोध प्रकट किया।

तो उग्र होगा आंदोलन

भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता कृष्णा रावत ने कहा कि अभी यह आंदोलन अपने शैशव अवस्था में है। यदि हमारी मांगों को शीघ्र ही नहीं माना गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र पाठक दिहायला, होतम सिंह रावत, जितेंद्र रावत, गोपाल गुर्जर, देवेंद्र रावत, जवाहर सिंह रावत सहित कई लोग मौजूद थे।

उन्नत किस्मों को बनाने वैज्ञानिकों ने दिया जोर

मप्र में चने की रोग प्रतिरोधक की किस्मों को करना होगा विकसित

इन पर दिया जोर

- » चने की रोग प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने पर
- » बायो फोर्टिफाइट किस्मों के शोध करने पर जोर
- » मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उन्नत किस्मों को तैयार करना
- » चने पर लगने वाले विभिन्न रोगों पर प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करना

जबलपुर। संवाददाता

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में चना फसल पर शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अधिष्ठाता कृषि संकाय, डॉ. धीरेंद्र खरे ने कहा कि चना के आनुवांशिक स्तर पर सुधार की असीम संभावना है। चने में लगने वाले विभिन्न रोगों पर प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उन्नत किस्मों को बनाने पर जोर दिया जाए। संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जीके कौतू ने चना से जुड़े शोध और मौजूदा चुनौतियों पर अपनी बात रखी। संगोष्ठी में सेंटल जोन के 16 केंद्रों के चना विज्ञानिकों ने अपने 4 वर्षों के शोध कार्यों का जानकारी को विस्तार से रखा। संगोष्ठी में चना अनुसंधान की समीक्षा के लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. जीपी दीक्षित द्वारा गठित समिति की गई, जिसमें अध्यक्ष डॉ. एसके शर्मा, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर एवं क्यूआरटी के सदस्य डॉ. डीपी सिंह, डॉ. डीके शर्मा, डॉ. डीवी आहूजा और डॉ. पीकुमार ने आनलाइन अपने अनुभवों को रखा।

इसके साथ चना अनुवांशिकी और सुधार पर विवेचना की। विभागाध्यक्ष पौध प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग डॉ. आरएस शुक्ला ने क्यूआरटी के आयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के चयन का आभार व्यक्त किया। चना विज्ञानिक डॉ. अनीता बब्बर द्वारा विवि में चल रहे चना अनुसंधान कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की गई।

निर्यात पर प्रतिबंध से मंडी में गेहूं 200 रुपए क्विंटल सस्ता, फिर भी खुले बाजार में महंगा

-इस बार 3000 रुपए क्विंटल मिल रहा है गेहूं, भाव में जल्द हो सकती है गिरावट

मझदार में 2000 करोड़ का गेहूं निर्यात कारोबार

भोपाल। संवाददाता

गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद गेहूं निर्यात का हौवा महंगा पड़ता नजर आ रहा है। निर्यात में बूम के हल्ले से सरकारी खरीद का जरूरी खजाना नहीं भरा और आम उपभोक्ता को महंगा गेहूं खरीदना पड़ रहा है। अब निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे प्रदेश के निर्यात कारोबारियों में हड़कंप है। 10 हजार से ज्यादा ट्रक माल फंस गया है। स्थानीय व्यापारियों और किसानों के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दांव पर लगने से घबराहट का माहौल है। मंडियों में 200 रुपए क्विंटल दाम जरूर गिरे, लेकिन आम आदमी को आज भी 3000 रुपए क्विंटल ही गेहूं खरीदना पड़ रहा है। कारोबारियों के अनुसार, इन सरकारी निर्णयों से आम उपभोक्ता की रोटी महंगी हुई तो किसान भी ज्यादा कीमत के लालच में फंस गया है। कई किसानों के सौदे निरस्त होने की कगार पर हैं। अब उन्हें सरकारी दाम के आसपास ही माल बेचने को मजबूर होना पड़ेगा।

भुगतान को लेकर विवाद

वहीं, व्यापारियों ने जिन किसानों का माल उठा लिया था, वह शिपमेंट में उलझ गया है। उनके बीच भुगतान को लेकर विवाद होंगे। सरकार अपने नियंत्रण में शुरू से निर्यात नीति बनाती तो न गेहूं महंगा होता, न सरकार के गोदाम खाली रहते और न ही कारोबारी फंसते। सरकार की जल्दबाजी से किसान-कारोबारी और निर्यातक तीनों ही निर्यात के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अनाज, दलहन, तिलहन व्यापारी महासंघ समिति ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कांडला व मुंबई पोर्ट पर फंसे लोडेड ट्रक का माल शिप में लोड करने की अनुमति देने की मांग की है।

सालाना खरीद में लग रहा फटका

अप्रैल-मई में सरकारी खरीद, निर्यात के बाद भी सालाना गेहूं की खरीदी बड़ी मात्रा में होती है। इंदौर में ही यह 40-50 हजार टन होती है। निर्यात के हौवे से इन खरीदारों को 300 से 400 रुपए क्विंटल का फटका लग रहा है। गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध से व्यापारियों का करोड़ों का गेहूं बंदरगाहों पर फंस गया है। वे बंदरगाहों पर फंसे गेहूं के निर्यात की अनुमति मांग रहे हैं। ऐसा न होने पर उन्हें भारी नुकसान होगा।

ऐसे फंसा अरबों रुपए का गेहूं

वर्तमान में कांडला व मुंबई पोर्ट पर करीब 10 हजार ट्रक फंसे हैं। व्यापारियों का कहना है, इसमें 5 हजार ट्रक मप्र के हैं। इनमें करीब 1.25 लाख टन माल लदा है। इतना ही या इससे ज्यादा सौदों का माल लदान के लिए तैयार है। इसका भविष्य तय नहीं है। 2 लाख टन से ज्यादा के रैक जा चुके हैं। सभी को मिला लें तो प्रदेश में 2000 करोड़ का निर्यात प्रभावित होगा।

ऐसे बढ़ी मुश्किल सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए फ्री पॉलिसी कर सोचा कि किसान को गेहूं के अच्छे दाम मिल जाएंगे। सरकार की इस नीति का असर यह हुआ कि गेहूं के दाम बढ़ गए, व्यापारियों ने निर्यात के सौदे तय कर लिए। सरकार ने देखा कि व्यापारियों द्वारा मलेशिया, गल्फ कंट्री, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, जापान, इटली व यूरोपियन देशों में माल भेजा जा रहा है। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। व्यापारी ऊंचे दाम पर एक्सपोर्ट कर मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को लाभ हो रहा है, लेकिन देश की फूड सुरक्षा मुश्किल में लग रही है। गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्पादन में गिरावट आई और सरकारी खरीदी भी 50 प्रतिशत तक प्रभावित होने लगी तो सरकार ने एक्सपोर्ट प्रतिबंधित किया। अब सरकार चाहती है कि उसकी मंशा के अनुरूप ही निर्यात हो। जिन देशों की मांग आए, वहां सरकार के माध्यम से निर्यात किया जाए। इससे सरकार को भी कहने को रहे कि संकट के समय मदद की।

सस्ता गेहूं महंगा आटा, मिल को लाभ, किसान को घाटा

जबलपुर। सरकारी खरीदी केंद्र और मंडियों में गेहूं के दाम 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास हैं। ये दाम पिछले साल के बराबर ही हैं। इस तरह किसानों की आय में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। इस समय गेहूं के दाम के मुकाबले आटा का मोल 50 से 60 प्रतिशत तक ज्यादा है। 20 रुपए किलोग्राम किसानों से बटोरा जाने वाला गेहूं आम आदमी के रसोई का आटा बनने तक 30 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू जाता है। अनेक नामी कम्पनियां तो 35 रुपए किलो तक धड़ल्ले से कारोबार कर रही हैं। गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हुआ, लेकिन निर्यात पर रोक लगा दिए जाने से दाम नीचे उतरने लगे हैं। दो दिन पहले तक किसानों और अनाज-कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाला गेहूं अचानक नुकसान पहुंचाने लगा है। गेहूं के दाम में गिरावट के बावजूद आटा के कारोबार में लगे लोग चांदी पीट रहे हैं। पिछले साल तक कोविड का प्रभाव होने से आटे की दर 22-23 रुपए किलो के आस-पास रही। इस साल हालात बदलने के बाद भी आटा के दाम 30 रुपए के ऊपर है। कुछ नामचीन कम्पनियों का आटा 38 रुपए प्रति किलोग्राम भी है। आटा बनाने में कच्चा-माल के रूप में गेहूं का इस्तेमाल होता है, जो बाजार में अपेक्षाकृत कम दाम पर उपलब्ध है, लेकिन आटा-मिलर ने आटे का भाव कम नहीं किया है। उनकी ओर से कीमत बढ़ाए जाने के ही संकेत मिल रहे हैं।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का300 नर्सरियों पर फोकस

बागवानी का शौक होगा पूरा, अब सरकारी नर्सरियों से मिलेगी सहायता

भोपाल। संवाददाता

अगर आपको भी बागवानी का शौक है और गार्डनिंग के दौरान आप भी छोटी-छोटी समस्याओं से परेशान होते हैं तो अब प्रदेश सरकार आपकी इस समस्या का समाधान करने जा रही है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेशभर में बरसों-बरस से चल रही अपनी 300 नर्सरियों को सरकारी ढर्रे से उबारकर आम जनता के लिए बहुउद्देशीय बनाने में जुट गया है। इन्हें आधुनिक बनाने पर जोर है, तो जनता से जुड़ाव की कारगर रणनीति को भी लक्ष्य किया गया है। इनमें बीज-पौधे, मिट्टी, हरी-गोबर खाद, गमले और निराई-गुड़ाई-सिंचाई आदि के उपकरणों-संसाधनों के अलावा अब विशेषज्ञ सलाह और मालियों के संपर्क नंबर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपने घर के बाड़े, बालकनी और छत पर बागवानी का सपना देखने वाले पर्यावरण प्रेमी, आम लोगों को एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर हर तरह की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। विभाग की योजना है कि जल्द ही प्रदेशभर के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, हर नर्सरी का एक वॉट्सऐप समूह बनाया जाएगा, ताकि लोगों की किसी भी जरूरत या समस्या का त्वरित समाधान हो सके।

तय करेंगे जनता को कैसे जोड़ा जाए विभाग अपर संचालक कमल एस. किराड़ के अनुसार एक आंतरिक अध्ययन में पाया कि राज्य की शहरी व कस्बाई नर्सरी सालों से एक जैसे स्वरूप में चल रही हैं, बदलाव की जरूरत है। तय किया गया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा जैसे तमाम मेट्रोज में रहने वाले लोगों के लिए घरों, बंगले और अपार्टमेंट के प्लांटेशन की जरूरत अलग है। कस्बे और अंचल में किसानों और लोगों की प्राथमिकता अलग। इसी आधार पर नर्सरियों को तैयार किया जा रहा है। दूसरा हमारे यहां तीन तरह के मौसम ठंड, गर्मी और बरसात हैं, जिसमें अलग-अलग तरह के फल, फूल और सब्जी के पौधे-बीज रोपे जाते हैं। इनकी जानकारी लोगों को नहीं है, जागरुकता बढ़ाने के लिए नर्सरियों पर कई तरह की प्रतियोगिता और कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। इनमें आम जनता को आमंत्रित किया जाएगा। वहां वे अपने प्रश्न-जिज्ञासाओं को रख पाएंगे और व्यावहारिक रूप से काफी कुछ सीखने-समझने को भी मिलेगा।

विभाग और जनता दोनों का फायदा

उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के एसीएस,जेएन कांसोटिया ने कहा कि हम महसूस कर रहे थे कि सरकारी नर्सरी आम नागरिकों से दूर हैं। केंद्र सरकार की भी योजना है कि अब बागवानी विभाग को बहुद्देश्यीय बनाकर जनता और विभाग दोनों का फायदा है। इसी को देखते हुए पिछले छह महीने से योजना पर काम शुरू किया है। चरणबद्ध ढंग से नर्सरियों का स्वरूप जनउपयोगी बनाया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण का हिस्सा भी शामिल है।

मालियों की कमी दूर करने कार्यशाला

विभाग सरकारी फाइलों से योजना को हकीकत के धरातल पर उतारने चरणबद्ध प्रयास कर रहा है। पहले चरण में 18 से 35 वर्ष के बीच के 8वीं तक पढ़े-लिखे युवाओं को एक महीने का आवासीय माली का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। 10 मई को राजधानी में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संभाग व जिले से संयुक्त संचालक उद्यान, जिला अधिकारी उद्यानिकी और हर जिले की दो-दो नर्सरियों के इंचार्ज समेत 200 से अधिक अधिकारियों को योजना के तहत कौन से सुधार और बदलाव करने हैं, उसके बारे में बताया गया। उधर, नर्सरियों के कायाकल्प की भी योजना है।

-सीएम बोले-राष्ट्रीय स्तर पर फसलों के उत्पादन में मप्र अग्रणी, मध्यप्रदेश में कृषि के विविधीकरण की अपार संभावना

-शिवराज ने इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव को किया संबोधित

टमाटर उत्पादन के लिए प्रदेश के 11 जिलों का हुआ चयन

भोपाल। विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की एक जिला-एक उत्पाद योजना में 11 जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसान की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हम कृषि के विविधीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिकों, प्र-संस्करणकर्ताओं, निर्यातकों से सलाह लेकर इस दिशा में गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। टमाटर के साथ फल-फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती और उनके प्र-संस्करण एवं व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री चौहान होटल आमेर ग्रीन्स में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा नीदरलैंड ऐंबेसी के सहयोग से हुए इंटरनेशनल टोमेटो कान्क्लेव-2022 को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी वर्चुअली शामिल हुए। कॉन्क्लेव में उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वान डेन बर्ग, चेयरमेन एमपी एग्रो एंदल सिंह कंसाना, कृषि काउंसलर मिशेल वान एर्कल, कृषि विवि ग्वालियर के कुलपति कोटेश्वर राव और कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जेएन कंसोटिया मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिए केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं के साथ फल, पौध-रोपण, व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन, उद्यानिकी के विकास के लिए यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, मसाला क्षेत्र विस्तार, खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास, मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्र-संस्करण और उद्यानिकी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज अधो-संरचना विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में कृषि उत्पादन की लागत घटाने, कृषक को उपज का उचित मूल्य दिलाने, बेहतर बाजार व्यवस्था स्थापित करने और प्राकृतिक आपदा में कृषक को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराकर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रभावी कार्य जारी है।

प्रदेश में 11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से समाज स्वास्थ्यगत समस्याएं झेल रहा है। अब प्राकृतिक कृषि को अपनाने और उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपने खेत के एक भाग में प्राकृतिक खेती से उपज लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में मप्र अग्रणी स्थान पर है। संतरा और धनिया बीज उत्पादन में प्रदेश, देश में प्रथम है। साथ ही अमरूद, टमाटर, प्याज, फूलगोभी, हरी मिर्च, मटर, लहसुन, नींबू आदि के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। मैं स्वयं किसान हैं और अमरूद, अनार, आम की पैदावार लेते हैं। मेरे द्वारा 9 एकड़ क्षेत्र में 766 टन टमाटर की पैदावार ली गई। किसानों के आर्थिक संबल के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है।

उत्पादन से लेकर बाजार तक की बनाना होगी व्यवस्थाः तोमर

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों के उत्पादन से लेकर बाजार तक की व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा कि मप्र उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती में बहुत अग्रणी है। मप्र ने सिंचाई और कृषि उत्पादन में बहुत उन्नति की है। खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव वर्तमान समय की आवश्यकता है।

टमाटर प्र-संस्करण लगाएंगे किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल टोमेटो कान्क्लेव-2022 प्रदेश में टमाटर फसल और उसके निर्यात, भंडारण, प्र-संस्करण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राज्य सरकार विशेषज्ञों द्वारा विकसित रणनीति का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने एक जिला-एक उत्पाद में प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य, उद्योग उन्नयन योजना में टोमेटो सॉस इकाई की स्थापना के लिए सिंगरौली के लवकुश प्रजापति को 10 लाख 80 हजार रुपए, दमोह के नारायण सिंह को 11 लाख 46 हजार और दमोह के ही भूपेंद्र सिंह ठाकुर को टमाटर प्र-संस्करण के लिए 26 लाख 60 हजार रुपए का चेक प्रदान किया।

उद्यानिकी के हर क्षेत्र में हो रहा विस्तारः कुशवाह

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने टोमेटो कॉन्क्लेव-2022 के उद्घाटन-सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में उद्यानिकी के हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। आत्म-निर्भर किसान और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप पर आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव-2022 करने का निर्णय सितम्बर-2021 में लिया गया था। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के विकास की संभावनाएँ मौजूद हैं। प्रदेश के 11 जिलों में किसानों ने टमाटर की खेती को प्रमुखता से अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए इन जिलों में एक जिला-एक उत्पाद में टमाटर को लिया गया है। मध्यप्रदेश की पहचान उद्यानिकी हब के रूप में होगी। कॉन्क्लेव से प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। कॉनक्लेव में विषय-विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को अमल में लाएंगे।

किसानों को नई तकनीक से परिचित कराना जरूरीः मार्टिन

नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन बेन डेनबर्ग ने कहा कि किसानों को फसलों के उत्पादन से जुड़ी नई तकनीक का ज्ञान देना जरूरी है। भारत के साथ नीदरलैंड की पिछले 75 वर्षों से क्लोज फ्रेण्डशिप है। इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव-2022 से टमाटर उत्पादन में किसानों को लाभ मिलेगा। प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को सरल और सहज भाषा में उनकी आवश्यकताओं के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी दें। उद्यानिकी आयुक्त ई. रमेश कुमार ने कॉन्क्लेव की रूपरेखा से अवगत कराया। कॉन्क्लेव किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, नीदरलैंड की संस्था सॉलीडरीडाड और राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग ने किया।

कृषि एवं प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा में किया आह्वान

किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए करें प्रेरित

भोपाल। संवाददाता

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर विभागीय समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि हर हाल में शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। कोई भी हितग्राही लाभों से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भ्रमण के दौरान मैदानी निरीक्षण पर यदि लाभों से वंचित होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिये अभियान चलाकर प्रोत्साहित करने को कहा है। विभिन्न विभागों की समीक्षा प्रभारी मंत्री द्वारा की गई। मंत्री ने जिले में कृषि के कुल रकबे, उत्पादित फसलों के साथ ही खाद-बीज और उर्वरक की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

किसानों को करो प्रशिक्षित- कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि में बढ़ते रासायनिक उपयोग के दुष्परिणाम से बचने के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। उन्होंने इसके लिये प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित कर प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराने को कहा है। मंत्री ने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए।

अभियान चलाएं, घर-घर करें सर्वे

कृषि मंत्री ने शासन की योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे कर हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण करें और पात्रतानुसार उन्हें लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। योजनाओं का जरूरतमंद तक लाभ हर हाल में पहुंचे, इसमें किसी प्रकार गड़बड़ी न हो, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गौ-पालन और गौ-शालाओं का करें बेहतर संचालन

कृषि मंत्री ने कहा है कि सड़कों पर गौवंश दिखाई नहीं दे, इसके लिए जरूरी है कि गौ-पालन और गौ-शालाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जाए। गौ-शालाओं में पानी और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। गौ-पालन के लिए शासन द्वारा दी जा रही सहायता गौ-पालकों को उपलब्ध कराएं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)